Lifting ban on employment in PSUs for General Categories

*148. SHRI RAM GOPAL YADAV :
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to lift the ban on employment in all public sector undertakings for general categories;

(b) if so, the details thereof and by when the ban is likely to be lifted; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) No Sir, since there is no such ban currently in operation. The ban imposed in 1984 was relaxed in 1985.

(b) and (c) Do not arise.

Setting up of a Software Service Support and Education Centre by European Community and India

*149. SHRI B. K. HARIPRASAD : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the European Community and India have agreed to set up a Software Service Support and Education Centre to provide thrust to software exports to EC countries;

(b) if so, whether any decision has been taken about the location of this Centre; and

(c) whether Bangalore has been considered as a probable site because of the availability of infrastructural facilities and skilled manpower ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. R. KUMARAMANGALAM) : (a) to (c) Yes, Sir. It has been decided to set up Software Service Support and Education Centre at Bangalore.

New projects of West Bengal pending with Government for clearance

*150. SHRI SUKOMAL SEN :
SHRI SUNIL BASU RAY :

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that over 280 applications to set up new projects in West Bengal, are pending with Government for clearance;

(b) if so, at what stage of consideration these applications are; and

(c) by when these applications are likely to be cleared ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO) : (a) to (c) No application to set up new projects in West Bengal is pending with Planning Commission for investment approval.

राजस्थान में पाताल-तोड़ कुएं लगाए जाने का प्रस्ताव

*151. श्री गूल चन्द मीणा :
श्री मुहम्मद इस्हाक खान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में विश्व बैंक की सहायता से पाताल-तोड़ कुएं खोदे जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

छावनी बोर्डों को दिए जा रहे सर्विस चार्ज (सेवा प्रभार) की धनराशि

*152. **श्रीमती सुष्मा स्वराज :**
डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न नगरों के छावनी बोर्डों को पिछले कुछ वर्षों से "सर्विस चार्ज" (सेवा प्रभार) के रूप में कुछ धनराशि दी जा रही थी;

(ख) यदि हां, तो छावनी बोर्डों को "सेवा प्रभार" की यह राशि कब से दी जा रही थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि छावनी बोर्डों के लिए यह एक आय का साधन है जिससे वे अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करते हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस संबंध में कतिपय आपत्तियां उठाकर "सेवा प्रभार" की राशि के भुगतान पर पाबंदी लगा दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार स्थानीय विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए पाबंदी लगाए गए क्षेत्रों में घाटे को पूरा करने के उद्देश्य से कुछ प्रबंध करने का विचार रखती है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार विकास कार्य करने के लिए छावनी बोर्डों को वर्ष 1982-83 से सेवा-प्रभार अदा किए जा रहे हैं ।

(घ) और (ङ) बजट व्यवस्था में अत्यधिक कमी के कारण छावनी बोर्डों को देय सेवा-प्रभारों की पूरी राशि का भुगतान करना सरकार के लिए संभव नहीं हो पाया है । सेवा-प्रभारों की पूरी राशि का भुगतान, धन उपलब्ध होने के बाद ही किया जा सकेगा ।

लघु विकास केन्द्रों (मिनी ग्रोथ सेन्टर्स) की स्थापना

*153. **श्री राम जेठमलानी :**
डा. जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के विभिन्न भागों में, विशेषत: पिछड़े क्षेत्रों में, लघु विकास केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने केन्द्र स्थापित किए जाने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रस्ताव को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(घ) यदि नहीं तो जनवरी, 1993 तक देश में कुल कितने लघु विकास केन्द्र स्थापित किए गए हैं और शेष कितने केन्द्रों के कब तक स्थापित किए जाने का लक्ष्य है ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम्) : (क) से (घ) 6 अगस्त, 1991 को घोषित लघु, अति लघु और ग्राम्य उद्यमों को बढ़ावा देने और इन्हें सुदृढ़ बनाने के लिए नीति संबंधी उपायों के अनुसरण में ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के लिए एक एकीकृत बुनियादी सुविधाओं की विकास (प्रौद्योगिकी सेवाओं सहित) योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

Production of cement

*154. SHRIMATI VEENA VERMA :

SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE :

Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) the production of cement during 1992-93, so far;

(b) the comparative figures for 1990-91 and 1991-92; and

(c) whether there is any proposal for setting up or expansion of cement plants in Madhya Pardesh, Gujarat or Maharashtra; if so, the details thereof ?